

राष्ट्रपति संबोधन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए देश भर में ठोस कदम उठाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा-संबंधित निकायों, उनके कामकाज और परीक्षा प्रक्रिया के सभी पहलुओं में बड़े सुधारों की दिशा में काम कर रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि संसद ने परीक्षाओं में अनुचित साधनों के खिलाफ भी सख्त कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में पेपर लीक के कई मामले पहले भी सामने आए हैं और सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए सही अवसर प्रदान किए जाएं। राष्ट्रपति ने कहा कि चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हों या सरकारी भर्ती की प्रक्रिया सबमें पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी की आवश्यकता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जम्मू-कश्मीर ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में रिकॉर्ड मतदान दर्ज कर देश के दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में वोटिंग का एक दशक पुराना रिकॉर्ड टूट गया है।

उन्होंने कहा कि पिछले चार दशकों से कश्मीर में शटडाउन और हड़तालों के बीच कम मतदान हुआ और देश के दुश्मनों ने इसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर की राय के रूप में प्रचारित किया। लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने ऐसी सभी ताकतों को करारा जवाब दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि नई सरकार आगामी संसद सत्र में अपना पहला आम बजट पेश करने जा रही है, जो उसकी दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का एक प्रभावी दस्तावेज होगा और सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।

राज्यपाल

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति संबंधी बिल को राजभवन ने टिप्पणी के लिए सरकार के पास भेजा है और इस पर सरकार को ही फैसला लेना है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में राज्यपाल ने इस बिल को लेकर कृषि मंत्री ने बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राजभवन पर दोषारोपण करना गलत है। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि ऐसे में कृषि मंत्री का बार-बार ये कहना गलत है कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति की नियुक्ति को लेकर बिल मंजूरी के लिए राजभवन में अटका है। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्यपाल और सरकार के प्रतिनिधि की सहमति से कुलपति की नियुक्ति होती है। राज्यपाल ने कहा कि राजभवन इस बिल को राष्ट्रपति को भेजने पर विचार करेगा और देश में ऐसा पहली बार होगा। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि ये मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है और वे नियमों के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में भूमिहीनों को नौतोड़ भूमि देने में राजभवन को कोई आपत्ति नहीं है। इस मामले में सरकार से लाभार्थियों की संख्या पूछी गई है और जवाब मिलने पर राजभवन इसे मंजूरी देगा।

बाली

राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आर.एस. बाली ने कहा है कि राज्य सरकार निजी क्षेत्र के सहयोग से सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रणाली के तहत पर्यटन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ठोस कदम उठा रही है। चण्डीगढ़ में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित

करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। आर.एस. बाली ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन के माध्यम से प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने के अलावा युवाओं को स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए भविष्य में देश के अन्य स्थानों पर भी इसी तरह के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।

मौसम

प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं और राजधानी शिमला सहित अनेक क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई। इस वर्षा से तापमान में गिरावट आई है जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कल से राज्य के अधिकांश भागों में प्री-मॉनसून की वर्षा होने की संभावना जताई और 30 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले तीन दिन राज्य के अधिकतर भागों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान पांच जिलों शिमला, मंडी, बिलासपुर, सोलन व सिरमौर में भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में मॉनसून के जुलाई के पहले सप्ताह में दस्तक देने की संभावना है।

इस बीच, भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों के समीप न जाने की अपील की है।

.....